

कोई योजना नहीं है। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रघर वाले शीघ्राचार्यों की व्यवस्था करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयत्न ही नहीं उठता।

पेय जल की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष अनुदान

5642. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्बास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पेय जल की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान देने के लिए कहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्बास मंत्री (श्री सिकन्दर बल्ल) : जी, हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 लाख रुपये के प्रारम्भिक नियतन के अतिरिक्त 250 लाख रुपये और अनुदान के रूप में नियतन की मांग की है। राज्य के निष्पादन तथा अतिरिक्त नियतन के लिए निधियों की उपलब्धता की समीक्षा करने के बाद कथित कार्यक्रम के अधीन 114 लाख रुपये की और राशि का नियतन किया गया तथा राशि मुक्त कर दी गई है।

Rent paid for Post Office buildings in Banswara distt.

5643. SHRI HEERA BHAI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of sub-post offices and Branch Post Offices in Banswara District and whether rent for all the buildings, except one, has been paid;

(b) if so, the amount of rent paid so far therefore; and

(c) the amount allocated in last Five Year Plan for construction of

buildings for post offices, and the amount which lapsed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEV SAL): (a) Sub Post Offices—16 and Branch Post offices—128 Rent for all the buildings has been paid.

(b) Rs. 10626/- per annum.

(c) No amount was allotted in the last Five Year Plan for construction of buildings for Post Offices in Banswara District and hence there was no lapsing of funds.

केन्द्रीय स्कूलों में अंग्रेजी समाप्त किया जाना

5644. श्री राम बिलास पासवान : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्कूलों से अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में समाप्त करने का है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में समाप्त करने के लिये राज्यों को विवेक देने का है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृतिक नज्वालख में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकतकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना विभिन्न रूप से केन्द्रीय सरकार के स्वामी-पुस्तकालयों के अन्तर्गत की जा रही है ताकि उनके वाता-पिता के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रायः होने वाले स्थानांतरणों के